सोशल सिक्योरिटी नाऊ
पूरा काम, पूरा दाम
पूरी सुरक्षा, पूरा मान

सेवा में

प्रधानमंत्री महोदय, भारत

एक गैर-संकुचित, गैर-पक्षपाती सार्विक सामाजिक सुरक्षा के लिए अपील

सोशल सिक्योरिटी नाऊ (एसएसएन) में सक्रिय मजदूर संगठनों, जनांदोलनों, सामाजिक सुरक्षा के लिए अभियान चला रहे संगठनों, दलितों, आदिवासियों व सामाजिक रूप से वंचित समूहों के हम लोग जो समावेशी सामाजिक व आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, श्रम व कमजोर समुदायों की प्रतिष्ठा व सुरक्षा, लोकतंत्र और सहभागी निर्णय प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, आपसे मांग करते हैं कि :

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएसए) 2008 में व्यापक संशोधन किए जाएं। हमारी मांग है कि सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा में संशोधन किया जाए; अधिनियम की विषयवस्तु में सामाजिक सुरक्षा लाभों को शामिल किया जाए; सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भारत में रह रहे और काम कर रहे सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाए चाहे उनके रोजगार की स्थिति या स्वरूप कुछ भी हो, उनकी मजदूरी कुछ भी हो, वे किसी भी नस्ल या जाति के स्त्री या पुरुष हों; सभी मजदूरों को विवाद निपटारे की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए और एक पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित की जाए।

हम मांग करते हैं कि सरकार भारत में रहने और काम करने वाले सभी लोगों को एक मौलिक अधिकार के रूप में गैर-संकुचित, गैर-पक्षपाती सार्विक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के जरिए स्वास्थ्य की देखभाल, बाल अधिकारों की सुरक्षा, विकलांगता लाभों, प्रसूति लाभ, दुर्घटना व बीमारी चिकित्सा, बेरोजगारी लाभों, वृद्धावस्था पेंशन और आजीविका क्षति मुआवजे की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के जरिए दलितों के सामाजिक समावेशन, आदिवासियों के विस्थापन पर अंकुश, दलित, आदिवासी व

एसएसएन राष्ट्रीय सचिवालय :173 ए, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
फोन : -91-11-29541841/29541858/29542473, फैक्स : -91-11-29545442, ई-मेल : ssn@cec-india.org, वेबसाइट : www.socialsecuritynow.org; www.cec-india.org

महिलाओं के आवास व भूमि अधिकारों की रक्षा, प्रवासियों की समस्याओं और महिलाओं के गैर-उजरती श्रम की मान्यता जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि सरकार इस गैर-संकुचित, गैर-पक्षपाती सार्विक सामाजिक सुरक्षा के लिए जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करे क्योंकि भारत में रहने और काम करने वाले सभी लोगों का सामूहिक रूप से पैदा की गई संपदा पर बराबर अधिकार बनता है।

सामाजिक सुरक्षा लाभों का निजीकरण बंद करो।

हम मांग करते हैं कि सभी लोगों को जीवन-अनुकूल वेतन उपलब्ध कराते हुए आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए। यह जीवन-अनुकूल वेतन आवश्यकता आधारित और भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) तथा वेतन आयोग द्वारा केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतनप्राप्त कर्मचारियों की मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए और इसमें समय-समय पर संशोधन की व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार सुनिश्चित करे कि किसी भी कार्यस्थिति में काम करने वाले सभी मजदूरों को मूलभूत श्रम अधिकार मिलें और उन्हें परिभाषित व नियमानुसार रोजगार मिलें।

सरकार सुनिश्चित करे कि लाभान्वितों की सरल और दोस्ताना ढंग से शिनाख्त की जाएगी और यह प्रक्रिया अवरोधक व लोगों को बेदखल करने वाली नहीं होगी।

एसएसएन एनडब्ल्यूजी सदस्य का संपर्क विवरण

नाम :.....

पता :.....

टेलीफोन :.....

ई-मेल :.....

तारीख :.....

स्थान :.....

नोट :.....

सोशल सिक्योरिटी नाऊ (एसएसएन) भारत में चलाया जा रहा एक राष्ट्रीय अभियान है। इस अभियान की मांग है कि भारत में रहने और काम करने वाले सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया जाए। एसएसएन में लगभग 500 नागर समाज संगठन, जनांदोलन, ट्रेड यूनियन संगठन, किसान संगठन, दलित आंदोलन व अन्य संगठन शामिल हैं। इस अभियान की विशिष्टता यह है कि इसमें दलित, आदिवासी और अन्य सामाजिक रूप से

एसएसएन राष्ट्रीय सचिवालय :173 ए, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
फोन : -91-11-29541841/29541858/29542473, फैक्स : -91-11-29545442, ई-मेल : ssn@cec-india.org, वेबसाइट : www.socialsecuritynow.org; www.cec-india.org

वंचित समूह भी सक्रिय हैं और उनका दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक सुरक्षा भारत के सभी 'सामाजिक वर्गों' का जायज हक है।

हस्ताक्षरकर्ता

शांति पटेल, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं मुंबई के भूतपूर्व महापौर

उल्का महाजन, नैशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स (एनएपीएम)

बिंदराय इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च स्टडी ऐण्ड ऐक्शन (बिरसा)

सीबीसीआई कमीशन फॉर लेबर

सेंटर फॉर कम्युनिटी इकॉनॉमिक्स ऐण्ड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसायटी (सीईसीओईडीईसीओएन)

सेंटर फॉर ऐजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)

कॉर्नरस्टोन ट्रस्ट

दिल्ली फोरम

दिल्ली श्रमिक संगठन (डीएसएस)

फाउंडेशन ऑफ ऐजुकेशनल इनोवेशंस इन एशिया (फेदिना)

ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (एचआरएलएन)

इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट (आईएसआई)

जन संघर्ष मंच

लया

लोक संघर्ष मोर्चा

नैशनल कैम्पेन कमेटी फॉर अनॉर्गेनाइज़्ड सेक्टर वर्कर्स (एनसीसीयूएसडब्ल्यू)

नैशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स (एनसीडीएचआर)

नैशनल डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट (एनडीडब्लयूएम)

नैशनल फेडरेशन ऑफ दलित लैंड राइट्स मूवमेंट (एनएफडीएलआरएम)

नैशनल फोरम ऑन फॉरेस्ट पीपुल ऐण्ड फॉरेस्ट वर्कर्स (एनएफएफपीएफडब्ल्यू)

एसएसएन राष्ट्रीय सचिवालय :173 ए, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
फोन : -91-11-29541841/29541858/29542473, फैक्स : -91-11-29545442, ई-मेल : ssn@cec-india.org, वेबसाइट : www.socialsecuritynow.org; www.cec-india.org

नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन चाइल्ड ऐण्ड यूथ डेवलपमेंट (एनआईडब्यलूसीवाईडी)

निदान

निर्मला निकेतन

प्रगतिशील श्रमिक मंच (सीएसएन)

प्रोग्राम ऑन वीमेंस इकॉनॉमिक सोशल ऐण्ड कल्चरल राइट्स (पीडब्ल्यूईएससीआर)

यूडीडब्ल्यूएमएसएम

उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन (यूपीजीएमएस)

विज्ञान फाउंडेशन, वेस्ट कलेक्टर्स वर्कर्स यूनियन (डब्ल्यूसीडब्ल्यूयू)

वीमेंस वॉयस

यूथ फॉर यूनिटी ऐण्ड वॉलंटरी ऐक्शन (युवा)

एसएसएन राष्ट्रीय सचिवालय :173 ए, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
फोन : -91-11-29541841/29541858/29542473, फैक्स : -91-11-29545442, ई-मेल : ssn@cec-india.org, वेबसाइट : www.socialsecuritynow.org; www.cec-india.org